Online at: https://researchtrendsjournal.com **ISSN No:** 2584-282X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 1; Issue 1; 2023; Page No. 421-424

Received: 01-09-2023
Accepted: 03-10-2023

उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में कृषि बीमा का प्रदर्शन विश्लेषण

[1]कुमार ज्योति प्रकाश, [2]डॉ. अविनाश शर्मा

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]सह–प्राध्यापक, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: कुमार ज्योति प्रकाश

सारांश
भारत जैसे देश में कृषि मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक आपदाओं दोनों के नकारात्मक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। छोटे खेतों वाले व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि कार्यों से आय सीमित है, चाहे वे खाद्य या गैर-खाद्य फसलें ही क्यों न उगाएँ। नतीजतन, यह उद्योग जोखिम से भरा हुआ है। ये प्रतिकूल घटनाएँ, सबसे खराब स्थिति में, किसान आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि में योगदान कर सकती हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2012 में 13,754 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2004 में 18,241 किसानों ने अपनी जान दे दी, जो रिकॉर्ड में सबसे खराब साल था। 2000-01 और 2012-13 के बीच, भारत में प्रति 100,000 लोगों पर 1.4 से 1.8 किसानों की आत्महत्या की दर 12 साल की सीमा में थी। 1995 से 2013 के बीच भारत में औसतन 16,469 किसानों ने हर साल आत्महत्या की। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, दिसंबर 2000 से उत्तर प्रदेश में लगभग 1,500 किसानों ने आत्महत्या की है। इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य यह जांचना है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसान जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा का उपयोग कैसे करते हैं। अध्ययन के परिणाम तीन मुख्य विषयों के अनुसार संरचित हैं: भारत और उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सफलता, भारत और उत्तर प्रदेश में कृषि बीमा का प्रदर्शन, और जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में कृषि बीमा पर किसानों के विचार।

मुख्य शब्दः खाद्यान्न, आत्महत्या, कृषि बीमा, फसलें, प्रबंधन

1. प्रस्तावना

भारत के अधिकांश छोटे और सीमांत किसान कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं; ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं और ऐसा विकास करना चाहते हैं जिससे सभी को लाभ हो, तो कृषि और सतत विकास उद्देश्यों को साथ-साथ काम करना होगा। अगर भारत को सतत विकास उद्देश्यों को पूरा करना है और घटती कृषि भूमि जोतों के सामने कृषि स्थिरता बनाए रखनी है, तो उसे छोटे किसानों की कृषि संसाधन दक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय छोटे किसानों को एकीकृत, संसाधन-कुशल दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए जिसमें विभिन्न रोपण पैटर्न, अनुकूली खेती और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारी उपयोग शामिल है। अगर हमें भविष्य में सुरक्षित और प्रचुर मात्रा में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, तो कृषि भूमि प्रणालियों को हरित क्रांति पर केंद्रित उत्पादकता से "कृषि में हरित उपायों" में निहित स्थिरता में बदलने की आवश्यकता होगी।

कृषि उत्पादों के सकल मूल्य संवर्धन की उच्च स्तरीय समीक्षा भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार में चक्रीय प्रवृत्तियाँ रही हैं। 2014-15 में नकारात्मक 0.2% से लेकर 2016-17 में सकारात्मक 6.3% और 2018-19 में 2.9% तक, कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन लगातार घट रहा है। कृषि, वानिकी और मवेशी उद्योग सभी में 2014-15 से 2017-18 तक अनियमित वृद्धि दर रही, जबकि मछली पकड़ने का उद्योग 2012-13 में 4.9% से बढ़कर 2017-18 में 11.9% हो गया। तालिका 1 को दर्शाते हैं: सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 2015-16 में 15.3 प्रतिशत से लगातार घटकर 2018-19 में 14.4 प्रतिशत हो गया है। सकल मूल्य वर्धन में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों का योगदान 2015-16 में 15.3 प्रतिशत से लगातार घटकर 2018-19 में 14.4 प्रतिशत हो गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से सकल मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 2015-16 में 9.2 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 8.7 प्रतिशत होने के कारण हुई है। 2014-15 से 2017-18 तक तीन वर्षों के दौरान सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान 0.8 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत तक 0.1 प्रतिशत अंक बढ़कर हुआ है। पशुपालन क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन में योगदान 2012-13 से 2017-18 तक 4 प्रतिशत

रहा, जबकि वानिकी और लॉगिंग का योगदान 2017-18 में 1.2 प्रतिशत.

किसानों और ग्रामीण समुदायों ने अपने दम पर जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए पीढ़ियों से कई तरीके विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, वे जल संरक्षण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में दीर्घकालिक निवेश कर सकते हैं, या वे फसलों और फसल किस्मों का मिश्रण उगा सकते हैं और फसल रोपण की तिथियों को अलग-अलग कर सकते हैं। कई किसान परिवार अपनी आय को बढ़ाने और कृषि आय पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए गैर-कृषि रोजगार में भी संलग्न होते हैं या गैर-कृषि व्यवसाय चलाते हैं। किसान नुकसान को कम करने के लिए भोजन, पशुधन, बचत और अन्य परिसंपत्तियों का भंडार रखते हैं, जिसका वे उपभोग कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर बेच सकते हैं। वे ऋण पर भी भरोसा कर सकते हैं, और स्थानीय स्वयं सहायता समूह और परिजन सहायता नेटवर्क सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। हालाँकि ये तरीके कई लगातार और विशिष्ट जोखिमों के प्रबंधन में काफी प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन वे मध्यवर्ती जोखिमों के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान करते हैं और बड़े सूखे या तूफान जैसे विनाशकारी जोखिमों के लिए पूरी तरह से विफल हो सकते हैं जो एक ही समय में कई किसानों, समुदायों और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इन प्रणालीगत जोखिमों को प्रबंधित करना विशेष रूप से कठिन है क्योंकि स्थानीय ऋण बाजार और समुदाय और परिजन सहायता नेटवर्क तब सामना नहीं कर सकते जब सभी को एक साथ मदद की आवश्यकता होती है। जिनके पास वापस आने के लिए सबसे कम संपत्ति होती है, वे आम तौर पर सबसे कम सामना करने में सक्षम होते हैं, और आवर्ती आय के झटके और संपत्ति का नुकसान उन्हें गरीबी में फंसाए रख सकता है (कार्टर और बैरेट, 2006)। प्रणालीगत जोखिम एफएसपी और कृषि व्यवसायों के लिए भी एक समस्या है जो किसानों को ऋण और कृषि इनपुट प्रदान करते हैं और उन्हें ऋण और अवैतनिक बिलों पर बड़े पैमाने पर चूक का सामना करना पड़ सकता है। जब किसी आपदा के कारण कच्चा माल दुर्लभ हो जाता है, तो कृषि व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, एफएसपी और कृषि व्यवसाय छोटे किसानों की सेवा करने के लिए कम इच्छुक हैं, जिन्हें वे बहुत जोखिम भरा मानते हैं। जलवायु परिवर्तन कृषक परिवारों और समुदायों को और भी अधिक जोखिमों के सामने उजागर करता है, जिसमें भयावह जोखिम भी शामिल हैं।

2. साहित्य की समीक्षा

डैनियल एडू अंक्राहऔर अन्य (2021) पृष्ठभूमि मौसम संबंधी जोखिम कृषि उत्पादकता लाभ को बाधित करते हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर। कृषि बीमा जलवायु संबंधी खतरों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके बावजूद, ग्लोबल साउथ में छोटे किसानों के बीच कृषि बीमा की पहुंच कम है। इस अध्ययन में घाना में छोटे किसानों के बीच कृषि बीमा की पहुंच और स्वीकार्यता की जांच की गई। विधि अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों को शामिल करते हुए एक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया। हमने उत्तरी, वोल्टा और पश्चिमी क्षेत्रों में अध्ययन किया, जिसमें 5 जिलों के 7 समुदाय शामिल थे। हमने कुल 200 किसानों का नमूना लेने और साक्षात्कार करने के लिए बहु-चरणीय उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का उपयोग किया। कृषि बीमा उत्पादों के बारे में अपर्याप्त जानकारी दुर्लभ अपनाने की दर (64%) का सबसे अधिक बार बताया गया कारण है, इसके बाद ज़रूरत वाले लेकिन कम सेवा वाले क्षेत्रों (23%) में बीमा उत्पादों की अनुपलब्धता है। कुछ (5%) ने बीमा को महंगा बताया। स्वीकार्य लिंग, शैक्षिक स्तर, कम ज्ञान, सूचना विषमता और कृषि बीमा उत्पादों के बारे में गलत धारणाएं कृषि बीमा की स्वीकृति और पहुंच को प्रभावित करती हैं। सुरक्षा की भावना और जलवायु परिवर्तनशीलता का कम प्रभाव कृषि बीमा द्वारा गारंटीकृत महत्वपूर्ण लाभ थे। निष्कर्ष कृषि बीमा उत्पादों पर सीमित जानकारी कृषि बीमा की पहुंच और स्वीकृति में बाधा डालती है। अधिक बीमा कंपनियों को अधिक छोटे किसानों को नामांकित करने में घाना कृषि बीमा पूल (GAIP) के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने की सराहना करें।

फ़िलिप ब्रैनस्ट्रैंड (2014) किसानों को संभावित जोखिम जोखिम के लिए इन परिवर्तनों की लगातार निगरानी करनी चाहिए। वित्तीय जोखिम, संस्थागत जोखिम, बाजार जोखिम और उत्पादन जोखिम वे विभिन्न जोखिम श्रेणियां हैं जिनका किसान सामना करते हैं। उत्पादन जोखिम किसान के नियंत्रण से बाहर से आता है। फसल उत्पादन कृषि कार्यों के लिए प्राथमिक आय का आधार है, यही कारण है कि किसान के लिए अपने उत्पादन जोखिम का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। फसल बीमा एक ऐसा उपकरण है जो उत्पादन जोखिमों के परिणामों को कम करने में मदद कर सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, सरकारें कई अलग-अलग तरीकों से उत्पादन जोखिम का प्रबंधन करती हैं। कुछ देश उपज हानि के लिए मुआवजा प्रदान करते हैं, और कुछ सब्सिडी वाले फसल बीमा कार्यक्रम प्रदान करते हैं। स्वीडन सहित कुछ देशों ने यह जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप दी है, जो कृषि क्षेत्र को फसल बीमा प्रदान करता है। स्वीडिश किसानों को उपज के स्तर में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है, जो उच्च जोखिम जोखिम का संकेत देता है। यह जलवायु परिवर्तन पर निर्भर हो सकता है। स्वीडन में निजी कंपनियां केवल रीसीडिंग और ओलावृष्टि क्षति के लिए फसल बीमा प्रदान करती हैं। स्वीडिश किसानों के लगातार जोखिम से बचने को देखते हुए, निजी कंपनियां उन्हें फसल बीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। इसलिए इस अध्ययन का उद्देश्य स्वीडिश किसानों की फसल बीमा की पसंद से जुड़े कारकों की पहचान करना है। हम स्वीडिश किसानों के फसल बीमा का उपयोग करने के निर्णय का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित उपयोगिता सिद्धांत का उपयोग करते हैं।

3. डेटा का विश्लेषण और विवेचन

तालिका 1979-80 से 1984-85 के दौरान पायलट फसल बीमा योजना के प्रदर्शन को दर्शाती है। शुरुआती दौर में पीसीआईएस केवल 3 राज्यों में लागू था और फिर 1984-85 तक इसका दायरा बढ़कर 13 राज्यों तक पहुंच गया। यह 'क्षेत्र दृष्टिकोण' पर आधारित था इसलिए इस योजना के अंतर्गत कुल 691760 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इसमें 1984-85 तक 157.05 लाख रुपये के दावों के मुकाबले प्रीमियम के रूप में 196.95 लाख रुपये की राशि के लिए 6.27 लाख किसानों को भी शामिल किया गया।

कुल प्रीमियम दावा अनुपात 79.74 प्रतिशत था जो दर्शाता है कि कुल प्रीमियम संग्रह का लगभग 79.74% दावों या क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था। इस योजना के तहत दावा अनुपात वर्ष 1982-83 में अपने अधिकतम (238.46%) पर दर्ज किया गया था, उसके बाद 1981-82 में और फिर वर्ष 1983-84 में यह गिरकर 39.41% हो गया। 1984-85 में इसे पुनः बढ़ाकर

66.69% कर दिया गया। 1979 से 1984-85 तक पीसीआईएस के प्रदर्शन से राज्यों की संख्या के संदर्भ में इसके दायरे और कवरेज में बढ़ती प्रवृत्ति का पता चला, जिसका अर्थ है कि 13 राज्य इस योजना के तहत सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। कवर किया गया क्षेत्र, कवर किए गए किसानों की संख्या, एकत्रित प्रीमियम की राशि और बीमा राशि आदि में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 1982-83 में किसानों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हुई थी।

तालिका 1: 1979-80 से 1984-85 के दौरान पायलट फसल बीमा योजना का प्रदर्शन

वर्ष	संख्या राज्यों का	क्षेत्र ढका हुआ (हा)	किसानों ढका हुआ	जोड़ बीमा (लाख रूपये)	अधिमूल्य एकत्र किया हुआ (लाख रूपये)	दावा चुकाया गया (लाख रूपये)	दावा का अनुपात (%)
1979-80	3	13181	16265	130.3	5.53	5.29	95.66
1980-81	3	18703	23442	165.77	6.93	3.27	47.18
1981-82	8	24467	24625	202.82	7.55	9.64	127.68
1982-83	9	70729	50855	468.26	15.65	37.32	238.46
1983-84	11	87347	60349	653.64	22.15	8.73	39.41
1984- 85	13	477333	451464	4446.49	139.14	92.8	66.69
कुल	-	691760	627000	6067.28	196.95	157.05	79.74

स्रोत: भारतीय कृषि बीमा कंपनी की रिपोर्टों से संकलित

विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीसीआईएस उन किसानों की फसल की उपज की रक्षा के लिए बेहतर है, जिन्हें फसल की उपज में गिरावट के कारण ऋण चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य दोष यह है कि यह केवल स्वैच्छिक आधार पर ऋण लेने वाले किसानों को ही कवर करता है। इसलिए किसान पीसीआईएस में बीमा कराने से झिझकते थे।

व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस) 1985-99

यह योजना अल्पावधि ऋण से जुड़ी थी और इसका कार्यान्वयन "समरूप क्षेत्र दृष्टिकोण" पर आधारित था। ख़रीफ़ 1999 तक, इस योजना को 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाया गया था। ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी थे। पीसीआईएस और सीसीआईएस दोनों केवल उन किसानों तक ही सीमित थे जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण उधार लिया था। दोनों योजनाओं की मुख्य विशिष्ट विशेषता यह थी कि पीसीआईएस स्वैच्छिक आधार पर था जबकि सीसीआईएस भाग लेने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था। योजना की मुख्य विशेषताएं थीं:

1. इसमें अनिवार्य आधार पर खाद्य फसलें और तिलहन उगाने के लिए वित्तीय संस्थानों से फसल ऋण लेने वाले किसानों को शामिल किया गया। कवरेज फसल ऋण के 100% तक सीमित था, जो प्रति किसान अधिकतम 10,000/- रुपये था।
2. अनाज और बाजरा के लिए प्रीमियम दरें 2% और दालों और तिलहन के लिए 1% थीं। किसानों के हिस्से का प्रीमियम ऋण वितरण के समय एकत्र किया जाता था। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा देय प्रीमियम का 50% केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी गई थी। प्रीमियम और दावों का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 2:1 के अनुपात में साझा किया गया था।
3. यह योजना एक बहु एजेंसी प्रयास थी, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारें, बैंकिंग संस्थान और जीआईसी (चांद) शामिल थे।

तालिका में 1985-1999 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना का राज्यवार प्रदर्शन दिखाया गया है। दावों और एकत्र किए गए प्रीमियम के अनुपात में अत्यधिक विषम प्रवृत्ति देखी गई। गुजरात राज्य ने कुल दावों का उच्चतम अनुपात (58%) दर्ज किया। दावे का 58% भुगतान उन किसानों को किया गया जो मूंगफली (तिलहन) की खेती में लगे हुए थे। 1985 से 1987 के दौरान गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा। इसका मूंगफली किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए, उन्होंने 20.74% के दावा अनुपात का लाभ उठाया है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह केवल 5.72% के आसपास था। अन्य भाग लेने वाले राज्यों में, आंध्र प्रदेश ने अखिल भारतीय स्तर पर 25% प्रीमियम का योगदान दिया, लेकिन उन्हें कुल दावों का केवल 3.2% प्राप्त हुआ।

तालिका 2: 1985-1999 के दौरान सीसीआईएस का राज्य-वार प्रदर्शन

राज्य	प्रीमियम एकत्र किया गया		दावा		दावा-प्रीमियम अनुपात
	रु. अनुपात करोड़	% शेयर करना	रु. अनुपात करोड़	% शेयर करना	
गुजरात	64.45	16	1336.93	58	20.74
महाराष्ट्र	60.42	15	253.33	11	4.19
आंध्र प्रदेश	100.7	25	322.7	14	3.2
अन्य राज्य	177.24	44	3918.6	17	2.21
भारत	402.81	100	2305.04	100	5.72

स्रोत: भारतीय कृषि बीमा कंपनी की रिपोर्टों से संकलित

विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दावों का बड़ा हिस्सा गुजरात (20.74%), महाराष्ट्र (4.19%) और आंध्र प्रदेश (3.2%) में किसानों को भुगतान किया गया था।

तालिका 3. में सीसीआईएस का फसलवार प्रदर्शन दिखाया गया है। यह निम्नलिखित फसलों जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अनाज, तिलहन, मूंगफली, दालें आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। फसलों में, मूंगफली में 16.02% की लागत से सबसे अधिक नुकसान होता है, इसके बाद बाजरा (15.06%) होता है। और तिलहन (13.88%)। इसके अलावा, प्रीमियम में मूंगफली का हिस्सा 19% था लेकिन यह कुल क्षतिपूर्ति का 52.94% था। अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार कुल हानि लागत 9.29% थी।

तालिका 3: 1985-1999 के दौरान सीसीआईएस का फसल-वार प्रदर्शन

काटना	अधिमूल्य (%)	दावे (%)	का दावा करें अधिमूल्य अनुपात	दावा के रूप में जोड़ आश्वासन दिया
धान का खेत	57.88	31.38	3.12	6.24
गेहूँ	4.42	1.3	1.69	3.39
ज्वार	8.35	4.96	3.42	6.83
बाजरे	4.12	5.4	7.53	15.06
अन्य अनाज	1.39	0.66	2.69	5.38
सभी अनाज	76.16	43.7	3.3	6.6
मूंगफली	19	52.94	16.02	16.02
अन्य तिलहन	3.51	1.4	2.28	2.28
सभी तिलहन	22.51	54.34	13.88	13.88
दालें	1.33	1.96	8.5	8.5
सभी फसलें	100	100	5.75	9.29

स्रोत: भारतीय कृषि बीमा कंपनी की रिपोर्टों से संकलित

4. निष्कर्ष

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में खाद्य फसल किसानों के बीच जोखिम प्रबंधन रणनीति पर मुख्य ध्यान देने के साथ कृषि के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक प्रयास है। अध्ययन ने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। इससे पता चला है कि उत्तर प्रदेश विशेषकर नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, आगरा और फ़िरोज़ाबाद में किसानों के बीच जोखिमों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत पहलों के माध्यम से जोखिम को कम करने और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बदलते परिदृश्य में, नीतियों का पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन करना आवश्यक है और किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

5. संदर्भ

1. आई.दत्ता कार्तिकेय "कृषि प्रणालियों पर कृषि बीमा के प्रभाव पर एक अध्ययन" इंजीनियरिंग और प्रबंधन में प्रगति के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (IJAEM) खंड. 2021;3:1366-1368. www.ijaem.net ISSN: 2395-5252
2. एंड्रयू क्रेन-ड्रोश, एलिजाबेथ मार्शल, स्टेफ़नी रोश, ऐनी रिडल, जोसेफ कूपर और स्टीवन वालैंडर। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम प्रबंधन, ईआरआर-266, अमेरिकी कृषि विभाग, आर्थिक अनुसंधान सेवा, 2019.
3. एनजोलरास, जी., ऑबर्ट, एम. फसल बीमा कीटनाशकों के उपयोग को कैसे प्रभावित करता है? फ्रांसीसी खेतों से साक्ष्य। रेव एग्रीक फूड एनवायरन स्टड. 2020;101:461-485. https://doi.org/10.1007/s41130-020-00129-5
4. मदकी, एमवाई, काचेले, एच., और बवोरोवा, एम. विकासशील देशों में जलवायु जोखिम अनुकूलन रणनीति के रूप में कृषि बीमा: नाइजीरिया का एक मामला। जलवायु नीति. 2023;23(6):747-762. https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2220672
5. ममता स्वैन "भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए फसल बीमा" 2014
6. पंकज सिंह और अन्य "भारत में कृषि बीमा योजनाओं का विकास, वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन विश्लेषण: साक्ष्य की समीक्षा" सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नलआईएसएसएन: 0306-8293
7. बोगदान मार्ज़ा एट अल "कृषि बीमा और खाद्य सुरक्षा। नई जलवायु परिवर्तन चुनौतियाँ" doi: 10.1016/S2212-5671(15)01038-2
8. महाजन, श्रीकृष्ण और बोबडे, अमोल। क्या फसल बीमा कृषि में विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का एक उपाय है? : यह सतारा जिले के खटाव तालुका में प्रदर्शन है। अनुसंधान की समीक्षा. 2012;1:1-4.
9. आदित्य के सा, एमडी ताजुद्दीन खान और अन्य "फसल बीमा को अपनाना और प्रभाव: भारत से अंतर्दृष्टि" कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा. 2018;31(2):163-174. डीओआई: 10.5958/0974-0279.2018.00034.4
10. शांग यान और अन्य "जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के बारे में किसानों के आकलन का उनकी अपनाने की इच्छा पर प्रभाव" जर्नल ऑफ़ इंटीग्रेटिव एग्रीकल्चर. 2021;20(12):3323-3338
11. Gbigbi TM, Ndubuokwu GO. डेल्टा उत्तर कृषि क्षेत्र, डेल्टा राज्य, नाइजीरिया में फसल किसानों के बीच कृषि बीमा संरक्षण के निर्धारक। ईजी यूनिवर्सिटी. ज़ीरात फ़क. डर्ग. 2022;59(2):235-248, https://doi.org/10.20289/zfdergi.883004
12. मुथिथी किन्यांजुई, एमए एट अल "कृषि बीमा को अपनाने को प्रभावित करने वाले कारक: इमेंटी साउथ सब-काउंटी, मेरु काउंटी, केन्या में छोटे धारक किसानों का एक मामला" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च वॉल्यूम। 2, क्रमांक 06; 2018
13. विंसेंट एच. स्मिथ और अन्य "विकसित देशों में कृषि बीमा: हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं?" वॉल्यूम. 34, नंबर 3 (शरद ऋतु 2012), पृ. 363-390

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.